गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर हजारीबाग की बेटी कैप्टन शिखा सुरभि ने बुलेट पर खड़े होकर सलामी दी.

राज्य की 24 महिला किसान इजरायल से उन्नत कृषि तकनीक का प्रशिक्षण लेकर वापस रांची लौटीं.

महिला सशक्तीकरण, बालिका शिक्षा पर जोर व बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की हुई शुरुआत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर, 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना– आयुष्मान भारत का रांची से किया शुभारंभ.

एक सोच से हुआ बड़ा बदलाव

पिछले दिनों देश-राज्य स्तर पर महिला सशक्तीकरण की कई नायाब झलकियां देखने को मिलीं. देश के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली के राजपथ पर परेड से लेकर विभिन्न साहसिक करतबों में जहां देश की महिला शक्ति ने अपना हुनर दिखाया, वहीं अपने राज्य में भी युवाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. पिछले कुछ सालों में लगातार अवसर दिये जाने के कारण हमारी महिलाएं अब अपने हुनर को निखार रही हैं. अपने कौशल से जटिल कामों को हाथ में लेकर उनमें सफलता अर्जित कर रही हैं. इससे स्पष्ट है कि महिला हो या पुरुष, सबको बराबरी के अवसर दिये जाने की जरूरत है. अवसरों से ही परिणाम मिलते हैं और परिणाम देने में महिला हो या पुरुष दोनों हमेशा खरे उतरते दिखायी देते हैं.

रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखंड

कृषि के क्षेत्र में विकास हमारी प्राथमिकता है. अन्नदाता किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्य है. राज्य सरकार कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने जा रही है. इसका लाभ राज्य के 22 लाख 76 हजार लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेगा. राज्य के किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए हमारी सरकार ने चुनिंदा किसानों को इजरायल भेजने की व्यवस्था की है. हाल ही में 24 महिला किसान इजरायल से उन्नत कृषि तकनीक का प्रशिक्षण लेकर रांची लौटीं. इनमें से 20 महिला किसान संथाल परगना से हैं. इजरायल से लौटीं ये महिला किसान अपने-अपने इलाके में एक रोल मॉडल की तरह आम महिला किसानों को प्रशिक्षण देने में लगी हैं. यह न केवल कृषि का विकास, बल्कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी सरकार का एक सार्थक प्रयास है.

झारखंड में कृषि का पैटर्न ऐसा है कि यहां हमेशा से महिला किसान अपने पुरुष सहभागी के साथ कंधे से कंधा मिला कर खेती में हाथ बंटाती आयी हैं. नयी तकनीक सीख जाने से अब वो बीज, खाद, पानी, फसल बोने की तकनीक, उचित मात्रा में धूप की आवाजाही से लेकर भरपूर उत्पाद प्राप्त करने का गुर सीख गयी हैं. पूरी कृषि व्यवस्था में इसका बहुत बड़ा फायदा आनेवाले दिनों में देखने को मिलेगा. इससे पैदावार बढ़ने के साथ ही खेती की गुणवता पर भी भारी असर देखने को मिलेगा, जिसका फायदा अंततः राज्य के किसानों को ही होगा. एक छोटे से कदम, एक प्रगतिशील सोच से पूरी कृषि व्यवस्था पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव हमेशा इस बात के लिए याद किया जायेगा कि सरकार ने इस सोच में महिलाओं को शामिल किया.

हमारी सरकार ने बजट में भी महिला सशक्तीकरण के मानक तय कर दिये हैं. इसके पीछे दृष्टि यह थी कि योजनाओं के बजट में सामूहिक तौर पर महिलाओं की योजनाएं शामिल कर लेने से उसका तात्कालिक और स्पष्ट लाभ महिलाओं तक पहुंचने में अक्सर देर हो जाती है, लेकिन अब जेंडर बजट आ जाने से महिलाओं की कई समस्याओं पर सीधे तौर पर फोकस किया जाना संभव हो पाया है. इनमें शामिल योजनाएं महिला केंद्रित हैं और विभागीय समन्वय से योजनाओं का लाभ अब सीधे तौर पर महिलाओं को मिल रहा है. मेरी नजर में सिर्फ पढ़-लिख जाना ही महिला सशक्तीकरण नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, कामकाज की जरूरतें, बच्चों का स्वास्थ्य, टीकाकरण, सामाजिक अधिकार तथा आजीविका का अधिकार अलग से देना, ये सब मिलकर किसी महिला या महिला समाज की मजबूती के स्तंभ बनते हैं. हमने अपना पूरा ध्यान इन्हीं मुद्दों पर फोकस किया है. हम आनेवाले दिनों में भी महिलाओं की समस्याओं की तह तक जायेंगे और उन्हें सामाजिक बराबरी के स्तर पर लाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे.

नारी शक्ति-मातृ शक्ति के प्रति हमेशा से ही हमारे मन में विशेष सम्मान का भाव रहा है. उनकी क्षमताओं का लाभ परिवार, समाज राज्य को मिल सके, इसकी लगातार कोशिश हमारी सरकार द्वारा की जाती रही है. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का अधिक से अधिक गठन, उन समूहों का बैंकों से जुड़ाव, उनका आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ाव, उनकी कौशल वृद्धि एक सुविचारित कदम है. इससे हमारे राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. साथ ही अपने परिवार को आर्थिक सबलता प्रदान करने में सफल हो रही हैं. हमारी सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए एक लाख से ज्यादा सखी मंडलों के माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनों को रोजगार उपलब्ध कराया है.

महिला सशक्तीकरण के लिए नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, दुमका को पूर्णतः छात्राओं के लिए आरक्षित रखा गया है. महिला सशक्तीकरण एवं बालिका शिक्षा पर जोर देने तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना प्रारंभ की है. इस योजना के तहत जन्म से दो साल की होने पर बालिका के माता के खाते में पांच हजार रुपये जमा कर दिये जायेंगे. इसके अलावा पहली कक्षा में दाखिले पर पांच हजार रुपये, पांचवीं, आठवीं, 10वीं और 12वीं पास करने पर पांच-पांच हजार रुपये सरकार द्वारा बैंक खाते में जमा कराया जायेगा. साथ ही 18 से 20 वर्ष की आयु पूरी करने तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी के समय तीस हजार रुपये भी दिये जायेंगे. राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने तथा विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. राज्य के छात्र-छात्राओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने विगत चार वर्षों में 43 नये आइटीआइ एवं 13 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की है.

विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- आयुष्मान भारत का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा रांची में किया गया. इसका लाभ राज्य के 57 लाख परिवारों को मिलेगा. आयुष्मान योजना के तहत तीन महीने में 22 हजार से अधिक झारखंडवासियों का मुफ्त इलाज हो चुका है. बेरोजगारी मिटाने की दिशा में राज्य सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है. इसके अंतर्गत पिछले चार सालों में 35 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है. सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से युवाओं में नयी आशा का संचार हुआ है तथा प्रतिभा पलायन पर भी अंकुश लगाने में हम कामयाब हुए हैं.